

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के

तारांकित प्रश्न सं. 227 का उत्तर

मैंगलोर और बेंगलोर के बीच उच्च क्षमता वाली रेल लाइन

*227. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की यात्री और माल ढुलाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मैंगलोर और बेंगलोर के बीच एक समर्पित उच्च क्षमता वाली रेल लाइन स्थापित करने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन, समय-सीमा और बजटीय आवंटन सहित प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने दोनों शहरों के बीच मौजूदा रेल मार्ग में गति और क्षमता सीमाओं सहित चुनौतियों की पहचान की है और यदि हां, तो उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (घ) उक्त रेलवे लाइन से व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास में क्या लाभ मिलेंगे?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 11.12.2024 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 227 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाएं लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड तथा धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं का लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

मंगलूरु पहले ही श्रवणबेलगोला और अरसीकेरे तथा हासन के रास्ते बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है। हासन-मंगलूरु (183 कि.मी.) के बीच बड़ी आमामान वाले एकल लाइन खंड, जो मंगलुरु से बेंगलुरु खंड का हिस्सा है, को 2006 में कर्नाटक सरकार की प्रमुख हिस्सेदारी वाली एक विशेष प्रयोज्य योजना (एसपीवी) के माध्यम से पूर्ववर्ती मीटर लाइन को बड़ी लाइन खंड में परिवर्तित करके कमीशन किया गया था। यह खंड पश्चिमी घाटों से गुजरता है और इसमें तीखे मोड़ और ढलान हैं। यह लाइन एक महत्वपूर्ण लिंक है और मंगलोर बंदरगाह को कर्नाटक के भीतरी भागों से जोड़ती है। विशेष प्रयोज्य योजना (एसपीवी) की खराब वित्तीय स्थिति के कारण, रेल मंत्रालय ने इस लाइन को अपने नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव दिया है ताकि दोहरीकरण, विद्युतीकरण आदि जैसे क्षमता संवर्धन संबंधी कार्य शुरू किए जा सकें।

तदनुसार, बेंगलुरु और मंगलूरु के बीच दोहरीकरण के एक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को दो भागों यथा (i) मंगलूरु-हासन (247 किमी) और (ii) कुणिगल के रास्ते हासन-चिक्कबाणावर (बेंगलुरु) (166 कि.मी.) में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, बेंगलुरु-तुमकुरु (30 किमी) के बीच तीसरी और चौथी लाइन के लिए एक सर्वेक्षण को भी मंजूरी दी गई है।

पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 6159 किलोमीटर लंबाई की कुल 56 परियोजनाओं (19 नई लाइन और 37 दोहरीकरण) के सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 47,016 करोड़ रु. लागत की 3,840 कि.मी. कुल लंबाई वाली 31 परियोजनाएं (21 नई लाइन और 10 दोहरीकरण) योजना व कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 1,302 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 17,383 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इसका सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	21	2556	395	7592
दोहरी लाइन/ मल्टीट्रैकिंग	10	1284	907	9791
कुल	31	3840	1302	17383

कर्नाटक में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	835 करोड़ रु. प्रतिवर्ष
2024-25	7,559 करोड़ रुपए (9 गुना से अधिक)

2009-14 और 2014-24 के दौरान, कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथ को कमीशन करने/बिछाने का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अवधि	कमीशन किया गया कुल रेलपथ	रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	565 कि.मी.	113 कि.मी. प्रतिवर्ष
2014-24	1,633 कि.मी.	163 कि.मी. प्रतिवर्ष

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

कर्नाटक राज्य में रेल परियोजनाओं से मिलने वाले लाभों में अनिवार्य वस्तुओं और कृषि उत्पादों की तीव्र आवाजाही, प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, प्रदेश का सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यटन उद्योग का विकास और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि शामिल हैं।
